को उक्त दल के दौरे के फलस्वरूप कितना व्यय वहन करना पड़ा;

(घ) क्या उक्त दल ने कोई विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तैयार किया है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि उपर्युक्त भाग (घ) का उत्तर "ना" में है तो ऐसा प्रतिवेदन कब तक तैयार किए जाने की संभावना है और उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) एक त्रिपक्षीय शिष्ट मंडल ने औद्योगिक पुनर्संरचना से प्रभावित श्रमिकों के पुनर्वास कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड और हंगरी का दौरा किया था।

(ख) शिष्ट मंडल में केवल केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम एवं मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे।

(ग) इंग्लैण्ड और हंगरी के अलावा किसी अन्य देश का दौरा नहीं किया था। दौरे पर हुआ पूर्ण व्यय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) ने वहन किया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) दल ने सिफारिश की है कि भारत में औद्योगिक पुनर्संरचना से प्रभावित होने वाले श्रमिकों के पुनर्वास के लिए इंग्लैण्ड और हंगरी के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की जाए।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

Agreement for taking back spent fuel from the Tarapur Plant

*356. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in accordance with an agreement both USA and France are required to take back the spent fuel from the Tarapur Plant;

(b) whether it is also a fact that both USA and France have not adhered to the agreement so far; and

(c) if so, what are the reasons for their reluctance to take back the spent fuel in accordance with the agreement and what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY, DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): (a) As per the agreements in respect of the Tarapur Atomic Power Station (TAPS), the fuel supplied both by USA and by France is the property of Government of India.

(a) and (c) Do not arise.

आई॰आर॰एच॰पी॰ए॰ के अधीन प्रदान की गई स्वीकृति

*357. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में "पावस" नामक परियोजना प्रारंभ करने के प्रयोजनार्थ आई॰आर॰ एच॰पी॰ए॰ के अधीन 1988 में पांच वर्ष के लिए 90 लाख रूपये की राशि मंजूर की थी;

(ख) मंजूर की गई कुल राशि में से 30 जून, 1992 तक जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को कितनी राशि दी गई है;

(ग) क्या उक्त परियोजना की उपलब्धि लक्ष्य के अनुरूप रही है;

(घ) क्या उक्त विश्वविद्यालय ने इस परियोजना के संचालन में सहायता देने के लिए किसी विशेषज्ञ की मांग की थी; और

(ङ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किन-किन विश्वविद्यालयों में, विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत करके, अपने विशेषज्ञ भेजे थे और इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): (क) से (घ) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के तीव्रीकरण के अधीन फंक्शनल पॉलिमर का प्रयोग करके फोटो

असिस्टेड घाटर स्पलिटिंग के लिए 79.44 लाख रुपये की कुल लागत का एक यूनिट स्वीकृत किया गया है। 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस कार्यक्रम के लिए 73.00 लाख रुपये दिए हैं। कुछेक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। एक उच्च स्तरीय तकनीकी मानीटरिंग समिति के जरिये इस कार्यक्रम की प्रगति की निरंतर मानीटरिंग की जाती है।

(ङ) विभिन्न संस्थाओं में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के तीव्रीकरण के अधीन सहायता प्राप्त सभी कार्यक्रमों का ऐसी तकनीकी मानीटरिंग समितियों के जरिये मानीटरिंग की जाती है।

उत्तर प्रदेश में खाद्य तेलों की आवश्यकता

*358. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में खाद्य तेलों की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को वास्तव में कितना कोटा दिया गया;

(ग) क्या सरकार, त्यौहारों के अवसर पर उत्तर प्रदेश के खाद्य तेलों के कोटे में वृद्धि करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य तेलों की अपनी कोई आवश्यकता सूचित नहीं की है।

(ख) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश को खाद्य तेलों का आवंटन तथा उसकी उठाई गई मात्रा इस प्रकार है:

तेल वर्ष	आवंटन	उठाई गई मात्रा
1989-90	16050 मी॰ टन	4913 मी॰ टन
1990-91	7500 मी॰ टन	4587 मी॰ टन
1991-92	6000 मी॰ टन	578 मी॰ टन

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश का आवंटन बढ़ाने का सरकार का विचार नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने अपनी मांग नहीं जताई है और उनके द्वारा पहले आवंटित किए गए तेलों की बहुत कम मात्रा उठाई गई है।

भारतीय राजनयिक मिशनों रहित देश

*359. **श्री राम नरेश यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने देशों में भारतीय राजनयिक मिशन स्थापित नहीं किए गए हैं; और

(ख) उक्त देशों में निकट भविष्य में कब तक भारतीय मिशन स्थापित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र के 71 सदस्य देशों में अभी तक भारत के राजदूतावास नहीं है। एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

इन देशों में से 62 देशों के मामले में भारत के राष्ट्रीय हितों की देखभाल सहप्रत्यायन के जरिए आसपास के देशों में हमारे राजदूतावास संतोषजनक रूप से कर रहे हैं और केवल बूनी, दारूस्सलाम तथा ताजिकिस्तान के मामले में ही आवास भारतीय मिशन खोलने की जरूरत महसूस हुई है। शेष 9 देशों के साथ भारत के औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है।

विवरण

भाग—क— **सह प्रत्यायन के अन्तर्गत आने वाले देश**

क्रम॰ सं॰	देश का नाम	मिशन का नाम जहां से सह-प्रत्यापित किया गया है
1.	अल्बानिया	रोमानिया
2.	एन्टीगुआ और बारबूडा	त्रिनिडाड एण्ड टोबागो
3.	अजरबैजान	उजबेकिस्तान
4.	अर्मेनिया	यूक्रेन
5.	बहामास	संयुक्त राज्य अमरीका
6.	बारबाडोस	सूरीनाम
7.	बेलीज	मेक्सिको
8.	बोलीविया	पेरू
9.	ब्रूनी दारूस्सलाम	मलयेशिया
10.	बुर्किना फासो	घाना
11.	बूरून्डी	उगाण्डा
12.	कैमरून	नाईजीरिया
13.	केप वर्डे	सेनेगल
14.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	जाइरे
15.	चाड	नाइजीरिया
16.	कोमोरोस	मैडागास्कर